RAJHIN/2014/55262

sancharjagat.com



संचार जगत

दैनिक समाचार पत्र

sancharjagat.com | editorial@sancharjagat.com

वह अनमोल वचन हैं, जो हमारी सोच को सकारात्मक बनाते और जीवन को सही दिशा दिखाते हैं।

वर्षः 13 | अंकः 248 | जयपुर, बुधवार, 07 अक्टूबर , 2026 | मूल्यः 2.00 रूपए | पृष्ठ : 4

एसआईआर पर विपक्ष में छिड़ा घमासान

आप और डीएमके ने बनाई दूरी

संचार जगत



नई दिल्ली। चुनाव आयोग के खिलाफ संसद भवन से लेकर निर्वाचन भवन तक के मार्च में डीएमके और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के प्रदर्शन से दूरी बनाई। डीएमके ने पहले ही इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। दरअसल विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग, एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वह सड़कों पर उतर कर चुनाव आयोग की कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद मौजूद रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके ने इस प्रदर्शन से दूरी बना रखी है। पिछली बार जब जंतर-मंतर पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था, तब इसमें आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह आगे देखे जा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में भी लिया गया था। आम आदमी पार्टी अब भी कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर वाले प्रदर्शन के लिए लोगों को बुलाने में लगी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों के विरोध प्रदर्शन में नहीं दिखाई दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने मंगलवार के प्रदर्शन के लिए डीएमके को आमंत्रण दिया था। हालांकि डीएमके ने ही इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से डीएमके इंडिया गठबंधन से दूरी बना रही है।

वोट चोरी के मसले पर कांग्रेस सहित विपक्ष उतरा सड़कों पर

मार्च रोका तो बैठे धरने पर

संचार जगत

नई दिल्ली। राहुल गांधी समेत 19 दलों के विपक्षी सांसद दिल्ली में चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीन घंटे से ज्यादा समय से दिल्ली के आकाशवाणी कैंपस में धरने पर बैठकर एसआईआर मसले पर विरोध जताया। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 19 विपक्षी पार्टियों के सेव डेमोक्रेसी मार्च में शामिल थे। संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस जा रहे मार्च को पुलिस ने रोका, राहुल-प्रियंका को हिरासत में लेकर बस में बैठाया, तो वे उतरकर आकाशवाणी परिसर में पेड़ के नीचे बैठ गए। राहुल ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी में भाजपा की मदद की। आकाशवाणी से आयोग का ऑफिस 270 मीटर दूर है और राहुल वहां तक जाने देने की मांग कर रहे हैं। चुनाव



आयोग के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में पिछले पांच दिनों में सातवां प्रदर्शन है।

राहुल गांधी ने कहा कि 300 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आए थे। हम ज्ञानेश कुमार और उनके दो चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे। पुलिस ने हमें रोका। चुनाव आयोग से 50 गज दूर बैठाकर हमें जाने नहीं दिया। 300 सांसद ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार डरे हुए हैं। अगर जनप्रतिनिधियों से चुनाव आयोग नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब है। सवाल पूछने पर राहुल ने नाराजगी जताई और कहा कि क्या मैं आपको भाजपा का कार्यकर्ता लगता हूं। भाजपा जो बोले मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लोकतंत्र बचाने यहां खड़ा हूं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार और मोहन भागवत ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। देश के युवा ये बात जानते हैं। चुनाव को मोदी-शाह ने हाइजैक किया है और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है। यहां पुलिस वाले भी यही कर रहे हैं। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। जो इन्होंने देश के साथ किया है, वह देशद्रोह है।

बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार

अराजकता फैलाने का लगाया आरोप

संचार जगत



नई दिल्ली। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष के मार्च पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रहा है और अराजकता फैला रहा है। इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाल कर अपना विरोध जताया। इस बीच बीजेपी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राहुल गांधी को लॉन्च और रीलॉन्च करने के लिए अराजकता पैदा करने और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।

पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस की तरफ से एक प्रायोजित कोशिश की जा रही है कि देश में सत्ता कैसे बदली जाए और राहुल गांधी को सत्ता में कैसे बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रायोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं।

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को सत्ता में बैठाने का काम कुछ महीने पहले शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह सालों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस किसी तरह राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च करने की कोशिश करती रही है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद जब राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की तैयारी

संचार जगत



कोलकाता। शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इस मसले पर बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक, राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में नाम बदलने से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। प्रस्ताव के तहत पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग किए जाने की बात कही गई है। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार राज्य की ऐतिहासिक जड़ों और पहचान से जुड़ने के उद्देश्य से यह बिल लाने की तैयारी कर रही है। उनके मुताबिक, नाम बदलने का फैसला राज्य के इतिहास को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

फ्रांसिस हाल्जेन को मिला फिजिक्स नोबेल

स्टॉकहोम। बेल्जियम में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हैल्जेन को 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार अंतरिक्ष से धरती तक आने वाले बेहद ताकतवर न्यूट्रिनो को पकड़ने और उनके बारे में पता लगाने में अहम काम के लिए दिया गया है। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में न्यूट्रिनो पकड़ने वाली आइसक्यूब ऑब्जर्वेटरी बनाने का विचार दिया था।

फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग

छात्र उतरे सड़कों पर

संचार जगत



पेरिस। फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। वहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में छात्रों ने सैकड़ों स्कूलों को बंद कराया। फ्रांस में शिक्षकों की कमी को लेकर चल रहा यह आंदोलन हिंसक हो रहा है। आंदोलन के दौरान कई जगह छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया।

मायावती ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

आकाश आनंद की बीएसपी में फिर हुई वापसी

संचार जगत



नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की एक बार फिर वापसी हुई है। मायावती ने उन्हें फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करने का ऐलान किया है। इसके बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भावुक प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद ने मायावती को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें क्षमा किया और दोबारा राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी। आकाश ने लिखा कि इस भरोसे के लिए वह तहे दिल से आभारी हैं और इस जिम्मेदारी को कभी हल्के में नहीं लेंगे।

राज्यवर्धन राठौड़ ने चंद्रभान सिंह आक्या के पिताजी को दी श्रद्धांजलि



संचार जगत



जयपुर। कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पिताजी रामसिंह आक्या के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राठौड़ ने चंद्रभान सिंह आक्या और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुःख की घड़ी में संबल और शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

सरकार खेलों का बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध

संचार जगत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और ऋषियों की अनमोल धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ, संयमित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे नशे की लत को छोड़ें और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हुए विकसित भारत-विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें। अलंकार पीजी कॉलेज में 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी प्रयासों और वैश्विक कूटनीति की बदौलत संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतरा?ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह ज्ञान परंपरा मानव कल्याण का वैश्विक माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। इनकी ऊर्जा से ही हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार गांव में अटल ज्ञान केन्द्र खोल रही है।



जिन्हें ऑनलाइन क्लास, ई-लाइब्रेरी सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, हर पंचायत में खेल मैदान भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अब तक एक लाख 93 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं। एक लाख 18 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है। सवा लाख पदों के लिए भर्ती कलैंडर जारी किया जा चुका है। इस मौके पर उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे मेहनत करें, परीक्षा की तैयारी करें, राज्य सरकार उनके सपनों को नहीं टूटने देगी।

जयपुर में पंचायत चुनाव की वोटिंग का दिन बदला

संचार जगत

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दिन में बदलाव किया है। उसकी ओर से जारी नए शेड्यूल के मुताबिक पहले फेज की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग अब 23 अक्टूबर के बजाए 22 अक्टूबर को होगी, जबकि वार्ड पंच और सरपंच के लिए वोटिंग 25 अक्टूबर के बजाए 24 अक्टूबर को करवाई जाएगी। इसी तरह दूसरे फेज की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग 29 अक्टूबर के बजाए 28 अक्टूबर को होगी, जबकि वार्ड पंच और सरपंच के लिए वोटिंग 31 अक्टूबर के बजाए 30 अक्टूबर को करवाई जाएगी।

हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से छोड़ी कप्तानी

संचार जगत



नई दिल्ली। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। हरमनप्रीत की जगह स्मृति मंधाना टीम की नई कप्तान बन सकती हैं। हरमनप्रीत के नाम कई रिकॉर्ड हैं। इनमें बतौर कप्तान भारत को पहला महिला वर्ल्ड कप जीताना शामिल है। उनकी कप्तानी में टीम ने 2012, 2016, 2022 और 2026 एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। 2012 एशिया कप में हरमनप्रीत ने सिर्फ फाइनल में कप्तानी की थी। बाकी मैचों में मिताली राज ने टीम की कमान संभाली थी। हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि आज मैं सभी फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हूं। यह आसान फैसला नहीं है। इसमें सालों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल जुड़े हैं, जो जिंदगीभर मेरे साथ रहेंगे।

उनके नेतृत्व में भारत ने 2025 में पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता। हरमनप्रीत वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कप्तान बनीं।

सऊदी अरब में तैनात होंगी पाकिस्तान-तुर्किये की फौज

संचार जगते



रियाद। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने अब सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। सऊदी समर्थित यमनी सेना ने हूतियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान और तुर्किये भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में हैं। सोमवार को रियाद में मक्का रक्षा समझौते की इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने सामूहिक रक्षा व्यवस्था को सक्रिय करने और सऊदी अरब में सैन्य बलों की तेजी से तैनाती पर सहमति जताई। इससे पहले भी सऊदी ने पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी। हालांकि, पाकिस्तान ने सितंबर में मदद देने से इनकार कर दिया था।

पाकिस्तान ने तब कहा था कि उसकी सेना किसी दूसरे देश की जमीन पर युद्ध में शामिल नहीं होगी। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 अगस्त को मक्का में रक्षा समझौते पर साइन किया था। सितंबर में हूतियों ने यमन के लाल सागर तट पर तेजी से बढ़ते हुए मोचा शहर और बाब अल-मंदेब के आसपास के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था।

केंद्रीय कर्मचारियों की जेब हो सकती है भारी

डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द

संचार जगत

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। साल की दूसरी छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान इसी महीने में होने की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग के दौर में यह दूसरी बार होगा, जब सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान करेगी। इससे पहले अप्रैल महीने में भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए को दो फीसदी बढ़ाया गया था। वैसे तो सरकार ने पिछले साल जनवरी महीने में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन 2025 के नवंबर महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंस और समिति का गठन हुआ। इससे एक महीने पहले सातवें वेतन आयोग के आखिरी दौर में सरकार ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया था। सातवें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू करेगी तो जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार ने अप्रैल महीने में पहली बार डीए का ऐलान किया था। यह ऐलान जनवरी से जून छमाही के लिए किया गया था। डीए में दो पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई और इसकी गणना सातवें वेतन आयोग के तहत ही किया गया। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 60 फीसदी है।

अखिलेश की निगाहें अब 403 पर

सपा नहीं उतारेगी तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार

संचार जगत



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर चढ़े हुए सियासी पारे के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के दो और बीजेपी के आठ राज्यसभा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनना तय हो गया है। इससे पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी अपने तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, और विधान भवन पहुंचकर उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन दाखिल करेगा, लेकिन उससे पहले ही पार्टी प्रमुख ने इशारों में बता दिया कि अब उसकी नजर तीन पर नहीं बल्कि 403 पर है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इनमें पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव शामिल हैं, जो छठी बार राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनके अलावा रिलायंस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी धनराज परिमल नथवानी को भी मैदान में उतारा गया है। इन दोनों नेताओं ने पिछले 30 सितंबर को अपना-अपना नामाकंन दाखिल कर दिया था। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की इन 10 राज्यसभा सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल इसी साल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। 16 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का मंगलवार को आखिरी दिन है। इस बीच, अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से शिकायत है। आयोग मानता है कि जो बीजेपी का सदस्य है वही वोट डाल सकता है। बंगाल- यूपी में बूथ लूट लिया। कितने चुनाव लूटे हैं'। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।

सम्पादकीय
न निलंबन, न ही रोक

सर्वोच्च अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता के निलंबन की मांग खारिज कर दी और उनके कामकाज, फैसले लेने पर कोई 'अंतरिम रोक' तक नहीं लगाई, लेकिन इतनी चेतावनी जरूर दी है कि यदि चुनाव आयोग के भीतरी फैसले अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्णय या अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के फैसले 'सर्वसम्मति' से नहीं लिए गए होंगे, तो शीर्ष अदालत उन तमाम फैसलों को रद्द भी कर सकती है। एक संवैधानिक संस्था के कामकाज और भीतरी विसंगतियों पर सर्वोच्च अदालत की यह बेहद कठोर चेतावनी है। सर्वोच्च अदालत के ही एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने लाखों लाख लोगों का मताधिकार छीनने को 'संविधान की आत्मा' पर प्रहार माना है। संविधान नागरिकों के दो वर्गों की अनुमति नहीं देता। किसी भी नागरिक को, जो मतदाता रहा है, नोटिस दिए बिना और अंतिम फैसले से पहले मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा चुनाव आयोग नहीं चाहिए। सर्वोच्च अदालत के ही पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नरीमन ने सवाल उठाया है कि जब करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गए और अब भी यह प्रक्रिया जारी है, तो उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय 'मूकदर्शक' क्यों बना रहा? संविधान और उसके अनुच्छेदों के नाम पर यह कवायद चलती रही है, तो सर्वोच्च अदालत ने अपना ठोस फैसला क्यों नहीं दिया? अर्थात चुनाव आयोग, एसआईआर और सीईसी की भूमिकाओं और उनके मद्देनजर विरोध-प्रदर्शनों को नए आयाम मिल गए हैं। अभी तक राजनीतिक विपक्ष चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों के कथित शुद्धिकरण को 'वोट चोरी' मानता रहा था और निरंतर आंदोलित है, लेकिन आयोग के ही दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बाद अब सर्वोच्च अदालत के मौजूदा और पूर्व न्यायाधीशों ने भी तीखी टिप्पणियां की हैं, तो यह मुद्दा बेहद गंभीर और संवैधानिक औचित्य का बन गया है। रायता खूब फैलता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी यह रही है कि जिस फॉर्म 6 के साथ 'तकनीकी बदलाव' के संदर्भ में चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देता रहा था कि शीर्ष अदालत ने उसे 'उचित' करार दिया था, उस पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कह दिया कि सर्वोच्च अदालत ने किसी भी 'तकनीकी बदलाव' को मंजूरी नहीं दी। तो क्या चुनाव आयोग देश के सामने 'सफेद झूठ' बोल रहा था?

वन्यजीव संरक्षण: प्रकृति के साथ भविष्य की सुरक्षा



वन्यजीव किसी देश की प्राकृतिक संपदा भर नहीं होते, बल्कि वे उसके पारिस्थितिक तंत्र की जीवंत कड़ियाँ हैं। जंगल, घासभूमि, आर्द्रभूमि, नदियाँ और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तभी संतुलित रह सकते हैं, जब उनमें रहने वाली विभिन्न प्रजातियाँ सुरक्षित रहें। भारत जैव-विविधता की दृष्टि से दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में शामिल है। यहाँ हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट, थार के मरुस्थल से लेकर सुंदरबन और अंडमान-निकोबार तक विविध प्रकार के आवास पाए जाते हैं। ऐसे में वन्यजीव संरक्षण केवल कुछ दुर्लभ प्रजातियों को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और मानव जीवन की सुरक्षा का भी प्रश्न है। राजस्थान में कैद में पाले गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण को वैज्ञानिक तरीके से पुन: प्राकृतिक आवास में स्थापित करने के प्रयास इस बात का उदाहरण हैं कि भारत अब संरक्षण में पारंपरिक उपायों के साथ वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को भी महत्व दे रहा है। वन्यजीव संरक्षण का पहला और सबसे स्पष्ट महत्व जैव-विविधता की रक्षा है। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में किसी न किसी भूमिका का निर्वहन करती है। किसी प्रजाति का विलुप्त होना केवल एक जीव के समाप्त होने की घटना नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़ी अनेक जैविक प्रक्रियाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अस्तित्व के साथ उसके पूरे घासभूमि आवास का संरक्षण जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बाघ के संरक्षण ने भारत में बड़े वन क्षेत्रों, शिकार प्रजातियों और संपूर्ण खाद्य-श्रृंखला की सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। इसलिए किसी 'छत्र प्रजाति' का संरक्षण अनेक अन्य प्रजातियों के लिए भी सुरक्षा कवच बन सकता है। वन्यजीव पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकारी प्रजातियाँ शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करती हैं, परागणकर्ता पौधों के प्रजनन में सहायता करते हैं और अनेक पक्षी तथा छोटे जीव बीजों के प्रसार में योगदान देते हैं। यदि खाद्य-श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी कमजोर हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ सकता है। स्वस्थ वन और घासभूमियाँ जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और कार्बन को अवशोषित करने में भी योगदान देती हैं। इस प्रकार वन्यजीव संरक्षण जलवायु और पर्यावरणीय सुरक्षा से भी सीधे जुड़ा हुआ है। वन्यजीवों का संरक्षण मानव समाज के लिए अनेक पारिस्थितिकी सेवाएँ भी सुनिश्चित करता है। वनों और आर्द्रभूमियों का संरक्षण जल को संचित करने, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और तापमान को संतुलित करने में सहायता करता है। मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य परागणकर्ताओं का संरक्षण कृषि उत्पादकता से जुड़ा है। इसी प्रकार प्राकृतिक आवास कार्बन भंडारण में योगदान देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता करते हैं। इसलिए प्रकृति की रक्षा को केवल पर्यावरणीय दायित्व समझना पर्याप्त नहीं; यह खाद्य, जल और आजीविका की सुरक्षा का भी आधार है। वन्यजीव संरक्षण का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा होते हैं। यदि पर्यटन का विकास स्थानीय लोगों की भागीदारी और पर्यावरणीय सीमाओं के अनुरूप किया जाए तो संरक्षण और आजीविका एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त वन्यजीव भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का हिस्सा हैं। आने वाली पीढ़ियों को बाघ, हाथी, गोडावण, गैंडा, सिंह और अनेक पक्षी-प्रजातियाँ उसी प्राकृतिक परिवेश में दिखाई दें, यह हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हालाँकि वन्यजीव संरक्षण के सामने चुनौतियाँ गंभीर हैं। सबसे बड़ी चुनौती आवासों का क्षरण और विखंडन है। बढ़ती आबादी, कृषि विस्तार, खनन, सड़क, रेल, उद्योग और अन्य आधारभूत परियोजनाओं के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं। अलग-अलग हिस्सों में बँट चुके जंगल जानवरों की आवाजाही और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से हाथी, बाघ और तेंदुए जैसी बड़ी प्रजातियों के लिए वन्यजीव गलियारों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। आधुनिक आधारभूत ढाँचा विकास के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है। सड़क और रेल दुर्घटनाएँ, विद्युत लाइनों से टकराव तथा ऊर्जा अवसंरचना कई पक्षी और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए खतरा बन सकती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके संरक्षण के लिए केवल पक्षियों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा; उसके प्राकृतिक आवास में मौजूद खतरों को भी कम करना होगा। इससे स्पष्ट होता है कि संरक्षण नीति को प्रजाति-केंद्रित होने के साथ-साथ लैंडस्केप-केंद्रित भी होना चाहिए। मानव-वन्यजीव संघर्ष भी संरक्षण के सामने बड़ी चुनौती है। जब हाथी खेतों में प्रवेश करते हैं, तेंदुए आबादी के निकट दिखाई देते हैं या जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो स्थानीय लोगों के सामने वास्तविक आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यदि संरक्षण का लाभ स्थानीय समुदायों तक नहीं पहुँचता, तो संरक्षण के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है। इसी तरह अवैध शिकार और वन्यजीवों की तस्करी कुछ प्रजातियों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन इस चुनौती को और जटिल बनाता है क्योंकि तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न से कई प्रजातियों के पारंपरिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आगे की रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। सबसे पहले प्राकृतिक आवासों की रक्षा के साथ-साथ क्षतिग्रस्त आवासों का पुनर्स्थापन किया जाए। वन्यजीव गलियारों की वैज्ञानिक पहचान कर उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए। विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति में केवल किसी एक संरक्षित क्षेत्र को नहीं, बल्कि पूरे लैंडस्केप और वन्यजीवों की आवाजाही को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जहाँ वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त हो, वहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग, जीन बैंक, रेडियो-टैगिंग, कैमरा ट्रैप और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। गोडावण जैसे संकटग्रस्त पक्षियों के लिए प्रजनन और पुनर्स्थापन कार्यक्रम तभी सफल होंगे, जब उनके प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित रखा जाए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है।

विश्व कपास दिवस : सफेद सोने की गाथा!
कपास केवल वस्त्र नहीं, जीवन है



हर वर्ष सात अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक फसल का दिवस नहीं है, यह उस सफेद रेशे का उत्सव है जिसने सभ्यताओं को वस्त्र दिया, व्यापार को दिशा दी और करोड़ों कृषकों को जीवन दिया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इसका महत्व सोने से कम नहीं। कपास का इतिहास भारत से ही प्रारम्भ होता है। पाँच हजार वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी की सभ्यता में कपास के बीज और सूत के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिला एक चाँदी के बर्तन में लिपटा हुआ कपास का धागा इस बात का साक्ष्य है कि भारत ही कपास का पहला घर था। प्राचीन ग्रंथों में इसे 'कर्पास' कहा गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था कि भारत में एक ऐसा पौधा उगता है जो भेड़ से भी सुन्दर ऊन देता है। यह ऊन कोई और नहीं, कपास ही था। मध्यकाल में भारतीय मलमल, ढाके की मलमल और कालीकट के केलिको ने विश्व बाजार पर राज किया। अंग्रेजी शब्द केलिको कालीकट से ही बना है। मुगल काल में ढाके की मलमल इतनी महीन होती थी कि पूरा थान एक अँगूठी से निकल जाता था। यह सब भारतीय कृषक और बुनकर की कुशलता का परिणाम था। आज भी भारत कपास उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में भी बुन्देलखण्ड और पश्चिमी क्षेत्र में कपास की खेती होती है।

हम अक्सर सोचते हैं कि कपास केवल कुर्ता-पजामा या साड़ी बनाता है, परन्तु इसका उपयोग बहुआयामी है। कपास के रेशे से वस्त्र बनते हैं। बिनौले से तेल निकलता है जो खाने के काम आता है। बिनौले की खली पशुओं के लिए उत्तम आहार है। कपास के डंठल से कागज और ईंधन बनता है।

इसके पत्ते जैविक खाद बनाते हैं। यहाँ तक कि चिकित्सा क्षेत्र में शुद्ध कपास की रूई का उपयोग अनिवार्य है। एक किलो कपास से लगभग एक सौ पचास ग्राम बीज और आठ सौ पचास ग्राम रेशा मिलता है। उस रेशे से एक जींस और एक कमीज बन सकती है। सोचिए, आपके शरीर पर जो सूती वस्त्र है, वह किसी कृषक के पसीने से प्रारम्भ हुआ था। कपास का कृषक आज भी संकट में है। कपास की फसल को बहुत पानी चाहिए, परन्तु अनियमित वर्षा और घटता भूजल उसकी सबसे बड़ी शत्रु है। गुलाबी सुंडी नामक कीट हर वर्ष लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट कर देता है। बाजार में भाव का उतार-चढ़ाव भी कृषक को तोड़ देता है। कई बार लागत से भी कम दाम मिलता है। इसी पीड़ा को समझ कर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तम बीज, जैविक कीट प्रबन्धन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कपास के लिए विशेष मंडियों की व्यवस्था की जा रही है। वैज्ञानिकों ने बीटी कपास जैसी किस्में विकसित की हैं जो कीट प्रतिरोधी हैं, परन्तु जैविक और देशी किस्मों को बचाना भी आवश्यक है। देशी किस्म का कपास कम पानी में भी होता है और उसकी गुणवत्ता उत्तम होती है। विश्व कपास दिवस का एक उद्देश्य यह भी है कि कृषक को उसकी फसल का उचित सम्मान मिले। जब हम खादी और हाथकरघा का वस्त्र पहनते हैं तो हम केवल वस्त्र नहीं पहनते, हम एक कृषक के परिवार का भरण-पोषण करते हैं, एक बुनकर की कला को जीवित रखते हैं।आज जब सम्पूर्ण विश्व कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक मिश्रित वस्त्रों से जूझ रहा है, तब कपास पर्यावरण के लिए वरदान है। कृत्रिम रेशा मिट्टी में सैकड़ों वर्ष तक नहीं गलता, जल स्रोतों में सूक्ष्म प्लास्टिक छोड़ता है। इसके विपरीत कपास पूरी तरह से जैविक है, मिट्टी में मिल जाता है, पसीना सोखता है, शरीर को ठंडा रखता है। गर्म देश भारत के लिए सूती वस्त्र सबसे उपयुक्त है। आयुर्वेद में भी सूती वस्त्र को सात्विक माना गया है। यह त्वचा पर दुष्प्रभाव नहीं करता, बालकों और रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित है। विश्व कपास दिवस हमें चार संकल्प लेने को कहता है। पहला, देशी कपास को बचाएँ। गुजरात की कल्यान, महाराष्ट्र की वरलक्ष्मी और आन्ध्र की सुजाता जैसी देशी किस्में कम लागत में अधिक टिकाऊ हैं। दूसरा, जैविक खेती को बढ़ावा दें। रासायनिक दवाओं के स्थान पर नीम, गोमूत्र और जैविक खाद का प्रयोग करें। इससे मिट्टी बचेगी और कृषक का स्वास्थ्य भी। तीसरा, बुनकर को बाजार से जोड़ें। आज भी बुनकर बिचौलियों के कारण लाचार है। यदि सीधे कृषक से बुनकर और बुनकर से ग्राहक का सम्बन्ध जुड़ जाए तो दोनों को लाभ होगा। चौथा, खादी और हथकरघा को अपनाएँ। एक सूती खादी का कुर्ता पहनना केवल परम्परा नहीं, यह स्वदेशी, स्वावलम्बन और पर्यावरण रक्षा का संकल्प है। अंत में यही कहना उचित होगा कि कपास केवल एक फसल नहीं, यह हमारी संस्कृति का ताना-बाना है। जिस देश ने विश्व को वस्त्र पहनना सिखाया, उस देश का दायित्व है कि वह इस सफेद सोने को फिर से चमकाए। विश्व कपास दिवस पर हम प्रण लें कि हम अपने खेत, अपने खलिहान और अपने बुनकर को नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्हीं से भारत की असली पहचान बनती है।

लघु कथा
इन्द्रधनुष के नीचे

अक्टूबर 1938 के 'हंस' (संपादक: श्रीपत राय) के पृ. 94-95 पर नित्यानंद की यह रचना, जो 'विशाल भारत' (सितंबर 1938) से ली गई है, भूमिका में दोनों जगह 'लघु-कथा' (हाइफ़न सहित) कही गई है, 'लघुकथा' नहीं। उस समय यह शब्द प्राय: 'छोटी कहानी' के अर्थ में चलता था, आज की विधा-संज्ञा 'लघुकथा' के अर्थ में नहीं, यह हमारा अनुमान है। रचना में भी कई चरण, लंबा कालखंड और रूपकात्मक विस्तार है ('कितने देश पीछे छूट गए, कितने लोक लाँघ डाले'), जो आज की कसी हुई लघुकथा से अलग है। इसलिए इसे 'लघु-कथा' कहना इसके स्वरूप के अनुकूल भी लगता है। बाक़ी विद्वान जानकार इस पर प्रकाश डालें। श्री नित्यानंद की एक सुन्दर लघु-कथा सितंबर, 1938 के 'विशाल भारत' में प्रकाशित हुई है। इस लघु-कथा को सम्पूर्ण ही पाठकों के मनोरंजनार्थ यहाँ उपस्थित करते हैं [यह टिप्पणी 'हंस' के अक्टूबर 1938 में प्रकाशित है] — 'कवि और ज्ञानी, दोनों ही चले—उस छिपे धन की खोज में। उन्होंने सुन रखा था कि जहाँ इन्द्रधनुष ज़मीन पर खड़ा होता है, वहीं वह धन गड़ा रखा है। 'ज्ञानी साथ में कई यन्त्र ले गया। जहाँ कहीं इन्द्रधनुष देख पाता, गणित से उसकी परिधि नापकर, त्रिज्या और केन्द्र की खोजकर, उपयुक्त स्थान पर खोदने लगता। कवि घास पर लेटकर सूर्य-रश्मियों से खेलता। वे उसके चारो ओर नाचतीं और उसे कल्पना-लोक की कथायें सुनातीं। कवि को हरएक वनस्पति से परिचय हो गया, हरएक पशु-पक्षी की भाषा उसे आ गई और हवा के झकोरियों पर चढ़कर आते हुए प्रकृति के मूक सन्देशों को भी वह न-जाने कैसे समझने लग गया। 'एक दिन जब ज्ञानी गम्भीर, थका-माँदा ज़मीन के भीतर से निकला, तो उसके छिले-कटे हाथों में कुछ अजीब-से पत्थर थे। वह कवि का विकसित मुख देखकर कुँलसा-सा पड़ा, बोला— 'अकर्मण्य! आलसी! तुम्हें क्या हो गया है?

'तुम हमेशा यहाँ बाहर ही तो पड़े रहते हो और यहाँ मैं ज़मीन के भीतर तक धँस जाता हूँ। 'लेकिन ज़मीन की सतह पर भी तो कुछ मिल सकता है?' 'सतह पर क्या मिलेगा? पाने के लिए तो भीतर ही पहुँचना होगा। मुझे तो अभी तक ठीक स्थान नहीं मिला; पर मैंने कई अद्भुत आविष्कार किये हैं, और निश्चय है कि सफलता मिलेगी।' 'कवि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक वह रुक गया और ज्ञानी की बाँह पकड़कर इशारा करने लगा! एक और इन्द्रधनुष!

बदलाव का इंतजार

बालिकाएं स्त्रियां अभी भी अपेक्षित अधिकार से वंचितद्य समय बदला, तकनीक बदली, जीवन-शैली बदली, बाजार बदला और फैशन भी बदल गया। महिलाओं को उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों और प्रदर्शन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के नए-नए तरीके खोज लिए। किंतु दुखद प्रश्न यह है कि क्या समाज की मूलभूत सोच बदली? क्या बालिका शिक्षा शत-प्रतिशत हो गई? क्या दहेज प्रथा समाप्त हो गई? क्या स्त्री उत्पीड़न इतिहास बन गया?

दुर्भाग्य से इन प्रश्नों का उत्तर आज भी नकारात्मक है। अनेक समस्याएँ आज भी यथावत बनी हुई हैं, बल्कि कई मामलों में उन्होंने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी अपेक्षित सम्मान और अवसरों से काफी दूर दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में सुधार तो हुआ है, किंतु वह इतना व्यापक नहीं है कि समाज को संतोष हो सके।

हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि शिक्षा का प्रसार होगा तो समाज की कुरीतियाँ स्वत: समाप्त हो जाएँगी। स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी और बेटी को बोझ नहीं, अवसर माना जाएगा। कुछ क्षेत्रों में प्रगति अवश्य हुई है, किंतु धरातल पर तस्वीर अभी भी अधूरी है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर लगभग 46.4 प्रतिशत तक पहुँचा है, जो पहले 41 प्रतिशत था। यह सुधार उत्साहजनक है, किंतु इसका अर्थ यह भी है कि आधी से अधिक महिलाएँ अभी भी दस वर्ष की बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का एक कारण बाल विवाह, गरीबी, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी हैं। अनेक परिवार आज भी पुत्र की शिक्षा को निवेश और पुत्री की शिक्षा को व्यय मानते हैं। यही सोच आगे चलकर दहेज जैसी कुप्रथा को जन्म देती और इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि शिक्षा और आधुनिकता के दावों के बीच दहेज का दानव आज भी जीवित है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत 15,489 मामले दर्ज किए गए तथा दहेज से संबंधित घटनाओं में 6,156 महिलाओं की मृत्यु हुई। अर्थात प्रतिदिन लगभग 17 महिलाओं ने दहेज की कीमत अपने जीवन से चुकाई। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की व्यापक तस्वीर भी चिंता उत्पन्न करती है। वर्ष 2023 में देशभर में महिलाओं के विरुद्ध लगभग 4.48 लाख अपराध दर्ज किए गए। इनमें सबसे बड़ी संख्या पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामलों की रही, जो कुल अपराधों का लगभग 30 प्रतिशत है।

यह स्थिति केवल आँकड़ों की कहानी नहीं है; यह उन लाखों बेटियों, बहनों और माताओं की पीड़ा का दस्तावेज है जो आज भी भेदभाव, हिंसा और असमानता का सामना कर रही हैं। समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले ने कहा था यदि तुम शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। वहीं डॉ. भीमराव आंबेडकर का प्रसिद्ध कथन है कि किसी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की प्रगति से किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जिस राष्ट्र ने अपनी स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सीखा, वह कभी महान नहीं बन सकता। क्योंकि केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है; आवश्यक यह है कि बालिका शिक्षा को सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसरों से जोड़ा जाए।

जब तक बेटी को परिवार की उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, जब तक विवाह को आर्थिक लेन-देन का माध्यम समझा जाएगा, तब तक दहेज की मानसिकता समाप्त नहीं होगी। विडंबना यह है कि एक ओर हम महिला सशक्तिकरण के नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, दूसरी ओर कन्या के जन्म पर चिंता और विवाह के समय दहेज की चर्चा अभी भी अनेक घरों में सामान्य बात मानी जाती है। यह दोहरा सामाजिक चरित्र हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज आवश्यकता केवल कानूनों की नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की है। विद्यालयों में लैंगिक समानता के संस्कार, परिवारों में बेटियों के प्रति समान व्यवहार, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, दहेज लेने-देने वालों का सामाजिक बहिष्कार तथा पंचायत स्तर तक जनजागरण अभियान ही वास्तविक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

अधिकारियों को दिए आपसी समन्वय, प्रशिक्षण और समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश

संचार जगत

जयपुर। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। निदेशक, जनगणना कार्य, श्री बिष्णु चरण मल्लिक ने पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनगणना-2027 के प्रथम चरण में किए गए कार्यों तथा दूसरे चरण में प्रस्तावित जनसंख्या गणना की तैयारियों, कार्यप्रणाली, समय-सारणी, प्रशिक्षण एवं डिजिटल व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनगणना कार्य को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पन्न



कराएं तथा इसमें लगाए जाने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण समय पर उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में मलिक ने बताया कि प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के तहत भवनों, जनगणना मकानों एवं परिवारों की व्यवस्थित सूची तैयार करने के साथ आवास की स्थिति, छत की सामग्री, पेयजल के स्रोत, शौचालय जैसी सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी संकलित की गई। राजस्थान में 1,34,091 हाउस लिसिटिंग ब्लॉक्स (में हाउस-लिस्टिंग का कार्य केवल के माध्यम से पूरा किया गया है।

दूसरे चरण में के तहत प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी तथा सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं प्रवासन से संबंधित विस्तृत जानकारी संकलित की जाएगी।

राजस्थान के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सेल्फ एन्यूमेरेशन 10 से 24 जनवरी 2027, जबकि पॉपुलेशन एन्यूमेरेशन 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इसके बाद 28 फरवरी 2027 की रात बेघर आबादी की गणना तथा 1 से 5 मार्च 2027 तक रिवीजनल राउंड प्रस्तावित है। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे निर्धारित की गई है।

डिजिटल माध्यम से होगी गणना, सेल्फ एन्यूमेरेशन की भी सुविधा

बैठक में शामिल अधिकारियों ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली डिडिटल सेंसस होगी, जिसमें स्मार्टफोन पर उपलब्ध क्क्ष्र स्प्रुड्डद्यद्द, श्चश्च के माध्यम से आंकड़े डिजिटल रूप से दर्ज, सत्यापित एवं मॉनिटर करेंगे। दूसरे चरण में ष्टस्रूस्र के माध्यम से फील्ड कार्यों का एंड-टू-एंड प्रबंधन, रियल-टाइम प्रगति की निगरानी और डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, जबकि श्वक्र ष्टह्लद्गड्डह्लश्नह्र से प्रथम चरण में तैयार ॥स्रह्य के भीतर एन्यूमेरेशन ब्लॉक्स तैयार किए जाएंगे। नागरिकों को पहली बार सेल्फ-एन्यूमेरेशन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद उसका सत्यापन किया जाएगा।

सेल्फ-एन्यूमेरेशन की अवधि 15 दिन रखी गई है और ॥स्रह्र में दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। बैठक में करीब 1.80 लाख फील्ड कार्मिकों की समय पर उपलब्धता, पर्याप्त रिजर्व व्यवस्था, आवश्यक पदों को भरने, जनगणना अवधि में नियुक्त कार्मिकों के स्थानांतरण पर नियंत्रण तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया।

कवलां ग्राम पंचायत के चवरड़ा गांव में जहरीला चारा खाने से 14 भैंस और 2 गायों की मौत

संचार जगत

आहोर। कवलां ग्राम पंचायत क्षेत्र के चवरड़ा गांव में कच्ची ज्वार खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जहरीला चारा खाने के बाद अब तक 14 भैंस और 2 गायों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद पशुपालकों में चिंता का माहौल है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बीमार पशुओं का उपचार कर रही है। बताया जा रहा है कि कई अन्य पशु भी प्रभावित हैं, जिससे पशुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पशुपालकों ने प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग से प्रभावित पशुओं का तत्काल उपचार कराने तथा मामले की जांच की मांग की है।

जिला परिषद सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए वार्डवार अधिकारी एवं स्थान निर्धारित

संचार जगत

जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद् जयपुर के सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए वार्डवार सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं नामांकन प्राप्ति स्थलों का निर्धारण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वार्ड संख्या 1 से 10 के लिए मृणाल कुमार, विशेषाधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे तथा नाम निर्देशन पत्र रीको कार्यालय, सीकर रोड, रोड नं. 5, वीकेआई एरिया, जयपुर में प्राप्त किए जाएंगे। वार्ड संख्या 15 से 26 के लिए प्रीति चौहान, सहायक कलक्टर, आमेर (फास्ट ट्रैक), सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगी तथा नाम निर्देशन पत्र एसीईओ (पंचायत प्रकोष्ठ) कक्ष, जिला परिषद् कार्यालय, जयपुर में प्राप्त किए जाएंगे। वार्ड संख्या 11 से 14 एवं 51 से 57 के लिए बजरंग लाल स्वामी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर (दक्षिण), सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे तथा नाम निर्देशन पत्र हवामहल के पीछे स्थित कार्यालय उपायुक्त नगर निगम हवामहल-आमेर जोन, पुराना पुलिस मुख्यालय, जलेब चौक, में प्राप्त किए जाएंगे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 27 से 37 के लिए राकेश कुमार, द्वितीय उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-14, सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे तथा नाम निर्देशन पत्र पंचायत समिति कार्यालय, सांगानेर, जयपुर में प्राप्त किए जाएंगे। वार्ड संख्या 38 से 50 के लिए निशु कुमार अग्निहोत्री, अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), टी.ए.डी. (माडा) सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे तथा नाम निर्देशन पत्र कमरा नंबर 45, कलक्ट्रेट, जयपुर में प्राप्त किए जाएंगे।

जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : प्रमुख शासन सचिव

संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश



संचार जगत

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमंत कुमार गेरा ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रमुख शासन सचिव ने निस्तारण समय को कम करने के लिए जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कुल 17 शिकायतकर्ताओं से ई— जनसुनवाई की गई जिनमें से 8 परिवादियों को विभाग द्वारा आंशिक रूप से राहत प्रदान कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। श्री गेरा ने बाड़मेर के प्रताप सिंह की पेयजल सप्लाई नहीं होने, भीलवाड़ा के राजेंद्र के दोषपूर्ण जल बिल, सवाई माधोपुर के रुपेश के यहां प्रदूषित पानी, दौसा के विजय सिंह की हेडपंप मरम्मत, सीकर के कमलेश कुमावत द्वारा दो बिल अलग-अलग खाता संख्या से प्राप्त होने की शिकायतों को सुना और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता और गति दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

विकास की रफ्तार से बदलेगा अजमेर का स्वरूप- देवनानी

संचार जगत

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को रामभवन तिराहा पर आयोजित कार्यक्रम में जवाहर रंगमंच से ममता स्वीट्स तक 62.01 लाख रुपये की लागत से बनने वाली तथा 46.21 लाख रुपये लागत की जवाहर नगर मुख्य सड़क के निर्माण कार्यों का शुभारम्भ किया। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों सहित आसपास की कॉलोनियों के नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि मंगलवार को अजमेर उत्तर क्षेत्र में एक ही दिन में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का शुभारम्भ किया गया है। सुबह वार्ड संख्या 4 स्थित संत कंवर राम कॉलोनी में 50 लाख रुपये से अधिक लागत के सड़क कार्य शुरू किए गए तथा शाम को जवाहर नगर क्षेत्र में भी सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार से जो भी आवश्यकताएं हों, उनके लिए प्रयास होंगे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1869 लीटर घी किया सीज

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुरलीपुरा स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई

संचार जगत

जयपुर। 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावट के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर प्रथम क्षेत्र के मुरलीपुरा स्थित RP Agencies पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री अविचल चतुर्वेदी



एवं अभिहित अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम की टीम द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान से ब्रांड घी का नमूना लिया गया। घी की गुणवत्ता में मिलावट की आशंका के मद्देनजर मौके पर उपलब्ध 1869 लीटर घी को सीज किया गया। उक्त घी का निर्माण ञ्जष्टड्ड द्दह्श स्नशशस्र क्क्ष्स्रह्वह्लह्य, सोनीपत, हरियाणा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान से Gowardhan Cow Ghee ब्रांड के घी के भी नमूने लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के मतदान कार्यक्रम में संशोधन

मतदान, पंच-सरपंच के नामांकन, मतगणना एवं उपसरपंच चुनाव की तिथियों में बदलाव

संचार जगत

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के मतदान एवं मतगणना सहित पंच-सरपंच पदों के नामांकन एवं उपसरपंच चुनाव की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि प्रथम चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का मतदान अब 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को होगा, जबकि पूर्व कार्यक्रम में 23 अक्टूबर निर्धारित था। मतदान दलों का प्रस्थान भी 22 अक्टूबर से बदलकर 21 अक्टूबर किया गया है। पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन की तिथि 24 अक्टूबर से बदलकर 23 अक्टूबर, मतदान की तिथि 25 अक्टूबर से बदलकर 24 अक्टूबर तथा मतगणना की तिथि भी 25 अक्टूबर से बदलकर 24 अक्टूबर कर दी गई है। उपसरपंच का चुनाव 26 अक्टूबर के स्थान पर 25 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का मतदान 29 अक्टूबर से बदलकर 28 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। मतदान दलों का प्रस्थान 28 अक्टूबर से बदलकर 27 अक्टूबर होगा। पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन की तिथि 30 अक्टूबर से बदलकर 29 अक्टूबर, मतदान एवं मतगणना की तिथि 31 अक्टूबर से बदलकर 30 अक्टूबर तथा उपसरपंच का चुनाव 1 नवम्बर से बदलकर 31 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। तृतीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का मतदान 04 नवम्बर से बदलकर 03 नवम्बर 2026 कर दिया गया है। मतदान दलों का प्रस्थान 3 नवम्बर से बदलकर 2 नवम्बर होगा। पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन की तिथि 5 नवम्बर से बदलकर 4 नवम्बर, मतदान एवं मतगणना की तिथि 6 नवम्बर से बदलकर 5 नवम्बर तथा उपसरपंच का चुनाव 7 नवम्बर से बदलकर 6 नवम्बर 2026 कर दिया गया है।

हैप्पीनेस फेडरेशन के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए जयपुर के महापौर सुनील कोठारी

संचार जगत

जयपुर। हैप्पीनेस फेडरेशन द्वारा 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित होने वाले दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु आज जयपुर के महापौर श्री सुनील कोठारी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉ. आदित्य नाग ने श्री सुनील कोठारी से सौहार्दपूर्ण भेंट कर उन्हें कार्यक्रम की अवधारणा, उद्देश्य एवं सामाजिक सरोकारों से अवगत कराया। श्री कोठारी ने अत्यंत आत्मीयता और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों के मध्य प्रसन्नता, सकारात्मक जीवन-दृष्टि, सामाजिक समरसता एवं जनकल्याण जैसे विषयों पर सार्थक एवं आत्मीय संवाद हुआ।

डॉ. आदित्य नाग ने कहा, 'सुनील जी मेरे लिए जयपुर के प्रथम नागरिक होने के साथ-साथ बड़े भाई के समान अत्यंत आत्मीय व्यक्तित्व हैं। अनेक पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों एवं व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने मेरे व्यक्तिगत आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हुए समापन समारोह में उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। उनका यह स्नेह और आत्मीयता मेरे लिए अत्यंत सम्मान एवं प्रसन्नता का विषय है। इस आयोजन का जयपुर में होना अपने आप में विशेष महत्व रखता है।' सूची में जयपुर को



विश्व के सबसे खुशहाल शहरों में छठा स्थान मिला और वह ञ्जश्चश्च 10 में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर रहा। ऐसे में का यह आयोजन जयपुर की प्रसन्नता, जीवंत संस्कृति, सामुदायिक सौहार्द और सकारात्मक जीवन-दृष्टि की वैश्विक पहचान को और सार्थक आयाम प्रदान करता है।

पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

संचार जगत

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में जुगल किशोर, प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी, प्रमोद दिवाकर, प्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी तथा राजेश सैनी, प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी उपस्थित रहे। प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष एवं आचार संहिता प्रकोष्ठ एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर-पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्वाचन आयोग के 3 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस-नोट के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। बैठक में पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

एसीएस ने सीएसआर प्रतिनिधियों के साथ राजकीय विद्यालयों में विकास कार्यों पर की चर्चा

राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को मिलेगा सीएसआर का सहयोग

संचार जगत

जयपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में चम्बल फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल लिमिटेड एवं होंडा मोटर्स लिमिटेड कंपनियों के सीएसआर प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सीएसआर के माध्यम से सतत सहयोग उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में चम्बल फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल लिमिटेड (ष्टस्रष्टरु) द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लगभग 35 राजकीय विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित विकासात्मक कार्य किए जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान ष्टस्रष्टरु की ओर से पूर्व से ही कार्य किए जा रहे 57 राजकीय विद्यालयों में संचालित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार होंडा मोटर्स लिमिटेड के सीएसआर प्रतिनिधियों के साथ खैरथल-तिजारा जिले के 12 राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से राजकीय विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ-साथ आवर्ती व्यय में भी सतत सहयोग उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री यादव ने राजकीय विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में सीएसआर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कंपनियों से विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।



बैठक में एसई श्री जयकिशोर दुबे, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती सीमा शर्मा, उपायुक्त-सीएसआर श्रीमती सुमन देवी, उपनिदेशक-सीएसआर श्री महेन्द्र प्रताप गर्ग, ष्टस्रष्टरु के सीनियर मैनेजर-सीएआर श्री अमित शेखर, सहायक मैनेजर-सीएआर श्री अभिषेक पचौरी, सहायक प्रोग्राम मैनेजर-सीएआर श्री तुषार सिंह तथा होंडा मोटर्स लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री भरत भूषण यादव उपस्थित रहे।

बजट का प्रभावी उपयोग कर विकास कार्यों में तेजी लाएं–मुख्य सचिव

बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, केंद्रीय सहायता प्राप्त करने और प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

संचार जगत



जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सरकारी व्यय की गुणवत्ता सुधारने और बजट राशि के बेहतर उपयोग से प्रदेश के विकास को गति देने पर जोर दिया। मंगलवार को शासन सचिवालय में वित्त व्यय विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक संबंधी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के प्रयास और मजबूत किए जाएं। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता वाले कार्यों में किया जाए, ताकि योजनाओं का बेहतर लाभ आमजन तक पहुंचे। मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी संबंधित विभागों के शासन सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। प्रस्ताव शीघ्र भिजवाए जाएं और प्रगति से अवगत कराया जाए। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की लंबित केंद्रीय सहायता और आगामी किस्तों की स्वीकृति के लिए संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रमुख शासन सचिवों को केंद्रीय मंत्रालयों से प्रभावी समन्वय करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास तेज करने को कहा। इन योजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें भी समय पर आयोजित करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने आर्थिक विकास को गति देने वाली प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रमुख परियोजनाओं को चिह्नित कर राज उन्नति पर सूचीबद्ध करने तथा उनकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा कर परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विद्युत अनुदान और कर्मचारी हितलाभों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस दौरान मुख्य सचिव ने पेंशन भुगतान से जुड़ी समस्याओं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लंबित भुगतान के मामलों के समाधान पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को वित्त विभाग के साथ समन्वय और स्पष्ट संवाद रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव, वित्त श्री वैभव गालरिया ने बताया कि योजनाओं के बजट के उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। 30 सितंबर, 2026 तक राज्य निधि और केंद्रीय सहायता सहित योजनाओं के कुल बजट का 41.16 प्रतिशत उपयोग किया गया है। शासन सचिव, वित्त (व्यय) डॉ. टीना सोनी एवं विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने बजट घोषणाओं पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई और वित्तीय स्वीकृतियों की स्थिति प्रस्तुत की। बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्रीय सहायता की स्वीकृति तथा आगामी किस्तें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानकारी भी दी गयी। प्रस्तुतीकरण में राज्य की आय, योजनाओं एवं सेवाओं पर व्यय, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय और वेतन-पेंशन सहित प्रमुख व्यय मदों का विवरण रखा गया। बैठक में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) डॉ. भारती दीक्षित सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एशियन गेम्स में रजत और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक विजेता यशवीर सिंह को दी बधाई

कहा:उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी



संचार जगत

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सचिवालय में जयपुर निवासी एवं एथलीट यशवीर सिंह से आत्मीय भेंट की। इस दौरान उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में रजत पदक तथा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर देश और राजस्थान का गौरव बढ़ाने पर यशवीर सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उपमुख्यमंत्री ने यशवीर सिंह की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यह सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। खेलों के क्षेत्र में यशवीर की उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और देश के लिए गौरव अर्जित करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा प्रतिभाओं ने विभिन्न खेलों में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश-प्रदेश का नाम रोशन किया है। यशवीर सिंह की उपलब्धि भी इसी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। उपमुख्यमंत्री ने यशवीर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय 'इंडियन हैयर एण्ड ब्यूटी कॉन्फ्रेंस' का उद्घाटन किया

सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय में प्राकृतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग हो - राज्यपाल

संचार जगत



जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कॉवेंशन सेंटर में राष्ट्रीय 'इंडियन हैयर एण्ड ब्यूटी कॉन्फ्रेन्स' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं में उद्यमिता का आत्मविश्वास जगाते हुए सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र व्यवसाय विकास का आव्हान किया। उन्होंने केश—प्रसाधन और सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय में प्राकृतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय के अंतर्गत 'मेक इन इण्डिया', 'लोकल फोर वोकल' से उद्यमिता विकास और इनसे युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का आह्वान किया। राज्यपाल ने सौंदर्य प्रसाधन और सैलून उद्योग में भारतीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ी विकास संभावनाओं पर कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने भारत के सैलून बाजार के एक लाख दो हजार करोड़ रूपये का होने की चर्चा करते हुए कहा कि सैलून उद्योग को भारतीय केश—विन्यास परम्परा के अंतर्गत विकसित किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उद्यमिता प्रोत्साहन आदि से कैसे लघु उद्यमियों को फायदा मिल सकता है, इस पर भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। श्री बागडे ने कहा कि हमारे यहां त्वचा को प्राकृतिक रूप में चमकदार बनाने और ठीक रखने के लिए एलोवेरा और शहद का इस्तेमाल होता रहा है। इसी तरह हमारे यहां आयुर्वेद में शरीर के बाहरी और अंदरूनी सौंदर्य के लिए बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। पेड़—पौधों के अर्क से, शहद से, हल्दी आदि से तैयार होते हैं। प्राचीन काल से केश और त्वचा के सौंदर्य के लिए इनका उपयोग लाभकारी रहा है। उन्होनें हैयर एंड ब्यूटी उद्योग की भारतीय दृष्टि और आयुर्वेद से जन जन को जोड़ने का आह्वान किया।

आशु सिंह लाछड़ी के हाथों हुआ 'डांडिया महारास' के पोस्टर का विमोचन



संचार जगत

जयपुर। जयपुर में नवरात्रि के रंग और डांडिया की खनक एक बार फिर देखने को मिलने वाली है। वैशाली नगर स्थित जानकी पैराडाइज में 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर को भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर होटल दरबार इन में डांडिया महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान आशु सिंह लाछड़ी ने महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। कार्यक्रम के ऑर्गनाइज़र पवन टांक सहित अन्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। चार दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में गरबा, डांडिया, संगीत और नवरात्रि के उत्साह का खास रंग देखने को मिलेगा। 16 से 19 अक्टूबर तक जानकी पैराडाइज में जयपुरवासी डांडिया की ताल पर झूमते और नवरात्रि के जश्न में शामिल होते नजर आएंगे। स्थान — जानकी पैराडाइज, वैशाली नगर, जयपुर।

अग्रसेन सोशल ग्रुप का चुनरी महोत्सव 11 को

माता महालक्ष्मी एवं दुर्गा माता को चढ़ाई जाएगी चुनरी, होगा प्रसाद वितरण



संचार जगत

कोटा। महाराजा श्री अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर अग्रसेन सोशल ग्रुप की ओर से रविवार को भव्य चुनरी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम निदेशक संभागीय महामंत्री सपना गोयल ने बताया कि 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रामधाम आश्रम में अग्रवाल समाज की कुलदेवी माता महालक्ष्मी एवं दुर्गा माता को विधिवत 151 फीट की चुनरी अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस धार्मिक आयोजन में समाजबंधु एवं श्रद्धालु सामूहिक रूप से माता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया जाएगा।

पोस्टर का किया विमोचन

संभागीय अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि चुनरी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन मंगलवार को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कोटा जिला अध्यक्ष विजय गोयल, संस्था के चेयरमैन संजय गोयल, उपेंद्र राय जैन ने किया। इस अवसर पर चेयरपर्सन पुष्पा गर्ग, सुनिता गोयल, उषा बंसल, कल्पना अग्रवाल, रानी अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, कमलेश गोयल एवं पदाधिकारियों ने समाजबंधुओं से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर चुनरी महोत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया।

राजस्थान में विधिक माप विज्ञान विभाग की बड़ी कार्रवाई

संचार जगत

जयपुर। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा पैकेज्ड सामग्री के संबंध में निर्धारित विधिक प्रावधानों की प्रभावी पालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ राज्यभर में विशेष निरीक्षण अभियान चला रहा है। अभियान के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुल 108 फर्मों का निरीक्षण कर विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए 2,61,000 रूपये की कम्पाउंडिंग की गई। जयपुर में 22 गोदाम स्थित विट्रोमेड हैल्थकेयर के निरीक्षण में फर्म का पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर 15,000 रूपये की कम्पाउंडिंग राशि अधिरोपित की गई। पैकेज पर निर्धारित अनिवार्य घोषणाओं में कमी पाई गई। इन कमियों में सुधार के लिए फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में आवश्यक सुधार एवं वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया।

जयपुर में 16 अक्टूबर से सजेगा डांडिया महोत्सव, 15 साल पूरे होने पर खास तैयारियां

संचार जगत



जयपुर। नवरात्रि के अवसर पर जयपुर में एक बार फिर डांडिया की धूम देखने को मिलेगी। SKJ Jewellers Dandiya Maharaas 2026 के पोस्टर का विमोचन संचार जगत के कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर आयोजन के डायरेक्टर एवं फाउंडर पवन टांक मौजूद रहे। आयोजन इस वर्ष अपने 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। डांडिया महोत्सव का आयोजन 16 से 19 अक्टूबर 2026 तक गांधी पथ, वैशाली नगर स्थित जांकी पैराडाइज में किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार चार दिवसीय इस आयोजन में डांडिया और गरबा के साथ मनोरंजन के कई आकर्षण देखने को मिलेंगे। इनमें महा आरती, बेस्ट कपल, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट डांसर, डांडिया किंग एवं डांडिया क्वीन, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस, DJ म्यूजिक, डांस एवं फूड स्टॉल, फेस्टिव डेकोरेशन और लकी ड्रॉ प्रमुख हैं।

आयोजन को लेकर युवाओं के साथ परिवारों के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। पोस्टर के अनुसार एंट्री टिकट 200 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, सिंगल बॉय के लिए 350 रुपए प्रतिदिन और VIP एंट्री 400 रुपए रखी गई है। टिकट की ऑनलाइन बुकिंग District by Zomato और BookMyShow के माध्यम से की जा सकती है। वहीं ऑफलाइन टिकट जांकी पैराडाइज टिकट काउंटर पर भी उपलब्ध रहेंगे। 15 साल से जयपुर में डांडिया की परंपरा को आगे बढ़ा रहे इस आयोजन में इस बार भी शहरवासियों के लिए नवरात्रि के रंग, संगीत और मनोरंजन का खास संगम देखने को मिलेगा।

जयपुर में होने वाले 'डांडिया महारास' को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।



संचार जगत

जयपुर। इसी कड़ी में माइल स्मिथ के फाउंडर और ष्टश्वह्व गणेश चौधरी के जयपुर स्थित कार्यालय में 'डांडिया महारास' के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर गणेश चौधरी ने डांडिया महारास के आयोजन को लेकर उत्साह जताया और आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। राजस्थान में नवरात्रि के दौरान डांडिया और गरबा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में 'डांडिया महारास' के आयोजन को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ती नजर आ रही है। पोस्टर विमोचन के साथ ही अब जयपुर में डांडिया महारास की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है।

किसानों के हित सर्वोपरि, उर्वरकों का समयबद्ध आवंटन एवं आपूर्ति सुनिश्चित करें – मुख्य सचिव

रबी सीजन में किसानों को मांग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश

संचार जगत



जयपुर। राज्य में आगामी रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को उनकी मांग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में मंगलवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय 'फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स' की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, आवंटन, आपूर्ति एवं गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की मांग के अनुरूप डीएपी एवं यूरिया का सुचारू एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के लिए आवंटित उर्वरकों की मात्रा का उचित एवं समयबद्ध आवंटन सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनियों से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि रबी बुआई के महत्वपूर्ण समय में प्रदेश में डीएपी एवं यूरिया की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी एवं आपूर्तिकर्ता कंपनियां आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने सभी जिलों में डीएपी एवं यूरिया के स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करते हुए, मांग एवं उपलब्धता की निरंतर मॉनिटरिंग करने तथा आवश्यकता के अनुरूप तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि प्रदेश में उर्वरक प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक उर्वरक वितरण केन्द्र पर कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में उर्वरक वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में 744 उर्वरक निरीक्षकों के माध्यम से जमाखोरी, कालाबाजारी, टैगिंग एवं अवैध भंडारण जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 'धरती माता बचाओ अभियान' के तहत गठित समितियों द्वारा नियमित बैठकें आयोजित कर उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 3 लाख 73 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 04 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 95 हजार मैट्रिक टन एनपीके तथा 2 लाख 09 हजार मैट्रिक टन एसएसपी का स्टॉक उपलब्ध है। उर्वरकों की आपूर्ति लगातार जारी है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को उर्वरकों का माहवार एवं कम्पनीवार आवंटन किया जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से परिवहन सेवाओं का हो रहा निरंतर विस्तार

संचार जगत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश में परिवहन सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीन नई रेल गाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति के अनुसार भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस (वाया कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं भरतपुर), हरिद्वार ओखा एक्सप्रेस (वाया अलवर, जयपुर, अजमेर एवं आबू रोड) और हरिद्वार वेरावल एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा।

स्वामित्व, प्रकाशक एवं संपादक : अवंतिका राठौड़ - पी.के. प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, 31, राम मंदिर के पास, पटेल नगर, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। कार्यालय : जे-17, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। संपर्क : 0141 463 7668 । ई-मेल : editorial@sancharjagat.com । आरएनआई नं. : RAJHIN/2014/55262। समाचार चयन के लिए पीआरबी अधिनियम के तहत जिम्मेदार। न्यायाधिकार क्षेत्र : जयपुर महानगर।